श्री जगमोहन : महोदय, वह.... की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : महोदय, कश्मीर तथा शेष भारत के लोगों के बीच बातचीत की प्रक्रिया आरम्भ हो जानी चाहिए।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मुझे उस पर भी आपत्ति व्यक्त करनी है। जहां तक भारत का संबंध है, किसी की कोई अलग पहचान या राष्ट्रीयता नहीं होनी चाहिए। यह गलत है। भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों तथा उप-संस्कृतियों के लोग रहते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर एकजुटता होना कठिन है। नहीं, यह संभव नहीं है।

अतः, मै यह मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया यह संकल्प एक स्वागत योग्य कदम है इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को समझकर तथा स्वीकार कर अविलंब शेष भारत के साथ उनकी सार्थक बातचीत आरम्भ करवाने के लिए वास्तविक तथा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि इस प्रस्ताव में छः महीने का उल्लेख किया गया है, मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि चुनाव सितम्बर अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में करवाए जायेंगे।

महोदय, मैंने जम्मू और कश्मीर के भूतपर्व राज्यपाल तथा इस सभा के माननीय सदस्य के विचारों को सुना है जिन्होंने बीते समय की अनेक घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जब हमें उस राज्य को उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए। बीते समय के बारे में चर्चा करने से कि वर्ष 1958 से 1996 तक क्या-क्या घटित हुआ, विश्व में अथवा जम्मू और कश्मीर राज्य में शान्ति नहीं लाई जा सकती है। यह मात्र एक निरर्थक प्रयास है, इससे आप केवल यह दिखा रहे हैं कि पिछली घटनाओं के बारे में कौन अधिक जानता है। इससे कोई हल नहीं निकलेगा। मैं अतीत की घटनाओं के बारे में ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहता।

पहली बार मैंने कश्मीर का दौरा किया है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इससे पहले मैं कश्मीर कभी नहीं गया था। जब पिछली बार मैंने कश्मीर जाने का निर्णय लिया था, तो उसी रात आपात्कात्त की घोषणा कर दी गई थी। तब मैंने अपनी हवाई यात्रा टिकट रद्द कर दी और वापस बैंगलोर, चला गया।

अपने दौरे के दौरान, मैंने विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। मेरी यात्रा का उद्देश्य था, प्राकृतिक आपदा के बारे में उस जगह जाकर अध्ययन करना और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में वहां के अधिकारियों से बातचीत करना। उसके साथ ही, मैंने वहां के अधिकारियों तथा राज्यपाल को यह भी संकेत दिया था कि मैं वहां के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए भी उतना ही इच्छुक हूं, यदि वे वास्तव में मुझसे मिलना चाहते हैं। उनको कोई विशेष आमंत्रण नहीं दिया गया था। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल कांफ्रेंस सहित सभी राजनीतिक दल सामूहिक रूप से मुझसे मिले और उनकी सर्वसम्मत मांग यह थी कि जम्मू और कश्मीर में शीघ्र चुनाव करवाए जाये। निश्चय ही, उनमें से एक राजनीतिक दल ने इस स्वायत्तता के प्रश्न पर मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया। उसी बैठक में, जिसमें भा.ज.पा. सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सभी इस बात से सहमत थे कि स्वायत्तता के प्रश्न, जिसका उल्लेख संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी किया गया है, की चर्चा इस समय नहीं की जानी चाहिए।

पहले हम चुनाव करवाते हैं। हम शीघ्र शान्ति चाहते हैं। हम पड़ौसी देश को इस बात की अनुमति नहीं देना चाहते कि वह कश्मीर के लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करें। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "हम इस देश का हिस्सा हैं। हम इस देश का अविभाज्य अंग हैं। हम पुनः बाहरी ताकतों को इस बात का अवसर नहीं देना चाहते कि वे यहां के वातावरण को दूषित करें।"

महोदय, यहां कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने अन्य देशों में दुष्प्रचार करने तथा गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर में हुए संसदीय चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने विश्व भर में ऐसी धारणा उत्पन्न करने की कोशिश की है। मैं इस बात के लिए पिछली सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि अनेक राजनीतक दलों द्वारा उनका बहिष्कार किए जाने के बावजूद उन्होंने चुनाव करवाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा यह सबसे उत्तम निर्णय लिया गया था। मैं कश्मीर के लोगों तथा इसके साथ ही वहां के प्रशासनिक तंत्र और वहां की सेना के लोगों की भी प्रंशसा करूंगा जिन्होंने मतदान केन्द्रों पर इतनी भारी संख्या में मतदान करवाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखा। मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार व्यक्ति इन चुनावों को ढोंग का नाम दे सकता है या फिर ऐसा कह सकता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे।

महोदय, मैं इस सभा के माध्यम से पूरे विश्व को यह बताना चाहता हूं कि विघटनकारी शक्तियों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि इन चुनावों में हेरा-फेरी की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है।

महोदय, बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र में 46.43 प्रतिशत मतदान हुआ था। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 41 प्रतिशत मतदान हुआ था। जम्मू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 48 प्रतिशत मतदान हुआ था। लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 83.26 प्रतिशत मतदान हुआ था अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 51.14 प्रतिशत मतदान हुआ था।

ऊधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 53 प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले। समूचे विश्व के लिए यह एक संकेत है कि लोग अपनी सरकार चाहते हैं। हमें इन सारी बातों का विश्लेषण खुले मन से करना चाहिए।

मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं- से पूछना चाहूंगा कि गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में, विगत संसदीय चुनावों में मुश्किल से 39 प्रतिशत मत पड़े थे। लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जहां किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, मतदान 42 अथवा 45 प्रतिशत से कम नहीं हुआ। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि लोग अपनी स्वयं की सरकार चाहते हैं। अतः हम चाहते हैं कि राज्य विधान सभा के चुनाव यथासंभव शीघ्र हो जाने चाहिए। मेरी रूचि इस बात में नहीं है कि कौन जीतने जा रहा है, कौन पार्टी चुनाव में भाग लेने जा रही है और किस प्रकार की गठजोड़ वहां पर होंगे। इस मुद्दे पर मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा। चाहे आप जीत रहे हों अथवा कांग्रेस जीतने जा रही हो या फिर जनता दल जीतने जा रहा हो, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा संबंध तो सिर्फ इस बात से है कि वहां चुनाव अवश्य होने चाहिए और सत्ता लोगों के हाथ में जानी चाहिए। उसके बाद स्वायत्तता के प्रश्न पर चर्चा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ की जा सकती है। वही ठीक और सही तरीका है। इस समय केन्द्र सरकार को किसके साथ बातचीत करनी चाहिए? मैं अलग अलग राजनैतिक दलों के हितों को देखते हुए काम नहीं कर सकता। केन्द्र सरकार स्वायत्तता किस सीमा तक दी जाए तथा कुछ अन्य सम्बद्ध मुद्दों के बारे में उन लोगों के साथ बातचीत करेगी जिन्हें लोगों का जनादेश मिलेगा। आपको पता है कि मेरे साथ की गई चर्चा के दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया। आपकी पार्टी के नेता स्वयं वहां थे। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने अनेक बातें मुझे बतानी शुरू की अर्थात् विकास तथा इसी तरह की अन्य चीजों के स्तर पर उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। मैं आपको बताता हूं कि आज उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन आम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो अपनी रोजी रोटी पर्यटन के जरिए कमाते थे। आज आम आदमी बेरोजगार है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनका जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से हो पा रहा है। उन्होंने ईमानदारी से इस बात का एहसास किया है कि उन्हें सामान्य जनजीवन चाहिए। वे पुराने कश्मीर को वापस जाना चाहते हैं। उनके लिए उसका अपना गर्व है। लोगों को इस प्रकार का वातावरण चाहिए। ऊधमपुर से जम्मू तक का रेल मार्ग, विद्युत परियोजनाएं और अन्य कई परियोजनाएं विभिन्न कारणों से ठप पड़ गई हैं।

महोदय, सरकार इस बात को भरपूर महत्व देने तथा यह सुनिश्चित करने को तैयार है कि लोग यह महसूस करें कि यह केन्द्र सरकार जहां तक कश्मीर का मामला है, उसके बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करने जा रही। चाहे जो भी वित्तीय बाधाएं हों। मैं इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने यह आश्वासन दे दिया है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : इसके साथ साथ लद्दाख और लेह के बीच भी कोई भी भेदभावन नहीं होना चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : बिल्कुल ठीक बात है, जम्मू और घाटी अथवा हिन्दू पण्डितों और मुस्लिमों के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वे एक परिवार की तरह रहे हैं। वे एक साथ कैसे रहते आए हैं यह देखकर और सुनकर मैं अचम्भित रह गया, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि मैं कश्मीरी लोगों की संस्कृति के बारे में सब कुछ जानता हूं। आज मुसलमानों ने गोमांस का सेवन करना बंद कर दिया है। वे गाय को एक पवित्र पशु मानने लगे हैं। वही वहां की परम्परा है। हिन्दू लोग सुअर का मांस नहीं खाएंगे। उन्होंने यह बात मेरी उपस्थिति में कही है। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं। मैं आपको बताता हूं कि यह संस्कृति कैसे विकसित हुई है। आप जानते हैं, इस संस्कृति, इस पुरानी संस्कृति और दोनों संप्रदायों के बीच इस बन्धन को हमने यानी कि हम राजनीतिज्ञों ने तोड़ा हैं। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने इस सम्मानीय सभा से केवल यह वायदा किया है कि मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की हर कोशिश करूंगा। और यही चीज वे लोग चाहते हैं।

जहां तक चुनावी प्रक्रिया अर्थात् मतदाता सूची, इत्यादि में भूलचूक का संबंध है, मैंने राज्य पाल और मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों तथा साथ ही साथ समाचार पत्रों, इत्यादि के जरिए लोगों से अनुरोध करते हुए इस बात का समुचित प्रचार किया जाय कि वे लोग, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैंत्र इस अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने अपने नामों को दर्ज करवा लें। मैंने राज्य पाल से दो अथवा तीन लाख और फार्मों को छपवाने तथा उन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों को देने के लिए कहा है।

कुछेक उग्रवादी युवकों ने मुझसे संपर्क किया है। वे भी चुनाव में भाग लेने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी कतिपय समस्याओं के बारे में बताया है। जब वे मुझसे मिले तो वहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे अतः गुप्त बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने राज्यपाल से अपने बगल में बैठने को कहा। मैंने उन युवकों से कहा कि आप पहले लोगों के पास जाइए, उनको अपनी निष्ठा का परिचय दीजिए और यदि जनता उन्हें वोट देती है तो उन्हें भी, जहां तक स्वायत्तता और अन्य मुद्दों का संबंध है, बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

हृदय परिवर्तन हुए हैं। पहले पड़ोसी देश द्वारा गुमराह किए गए कुछेक युवकों ने इसका एहसास किया है और वे समूचे जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग करना चाहते हैं।

कतिपय क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों इत्यादि को लेकर कुछ त्रुटियां एवं भूल चूक हुए हैं। ये सभी बातें वहां पर हैं। मैं सितम्बर के पहले इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। इसमें समय लगेगा और इसीलिए अभी हमें चुनाव को इसी रूप में होने देना चाहिए।

अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो बाद में इन सभी चीजों की जांच आगामी निर्वाचित सरकार द्वारा की जा सकती है। महोदय, जैसा कि मैं पहले वायदा कर चुका हूं, मैं चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगा। तिथि का निर्धारण करना उनका काम है। भारत सरकार सभी आवश्यक इंतजाम करेगी। हम डोडा जिले अथवा अन्य किसी भी अशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। हम अधिकतम सुरक्षा

प्रदान करेंगे और चाहेंगे कि आगामी चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतों का प्रयोग करें।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहां से अपना घर द्वारा छोड़कर अन्यत्र गए लोग अपना मत डालें?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह मुद्दा दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में उठाया गया था जिसमें श्री वाजपेयी भी शामिल थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां मतदाताओं की संख्या लगभग 96,000 है। इस बार हुए, संसदीय चुनावों में गरीब 30,000 लोगों ने वोट डले थे। उस समय कुछ भ्रम की स्थिति थी जब यह बात सामने आई कि यह कौन सत्यापित करेगा कि वे कश्मीर छोड़कर आए हैं। हमने डाक द्वारा मत देने की व्यवस्था को भी सरल बना दिया है। किसी प्रकार की बाधा का कोई सवाल ही नहीं होगा। हमने व्यवस्था को सरल बना दिया है और जो कोई भी डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता है, उसे यह व्यवस्था दी जाएगी। उन लोगों को भी किसी किस्म की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : जब तक आप उन्हें कोई मौका नहीं देंगे वे अपना वोट किस प्रकार डालेंगे?, उदाहरणार्थ वे दिल्ली में बैठे हैं। वे अपना नाम शामिल करवाने के लिए फार्म भरने हेतु कश्मीर घाटी नहीं जा सकते हैं। आप को दो चीजें करनी होगी। आप उन्हें दिल्ली में वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। वे फार्म भर सकते हैं और आप उनका सत्यापन कर सकते हैं। वह पहली चीज है। मतदान की डाक व्यवस्था से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आप उनके दिल्ली अथवा कलकत्ता अथवा चंडीगढ़ में या जहां कहीं भी वे हैं, वहां पर मतदान केन्द्र क्यों नहीं बनवाते हैं? उन्हें वहां जाकर मतदान करने दीजिए। 93,000 में से केवल 23,000 मतदाताओं ने अपने मत डाले।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मतदान केन्द्र कहां बनाए जाने हैं, कितने बनाए जाने हैं, इन्हें देश के बाहर या कश्मीर के बाहर बनाया जाना है, ये सब बातें चुनाव आयोग की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी बात पर भी पूरा गौर किया जाएगा। मैं बहस नहीं करने जा रहा। जहां तक कश्मीर के बाहर अथवा कश्मीर के भीतर मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने का संबंध है, यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर छोड़ी गई है। मैं चुनाव आयोग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता हूं। मैं केवल एक सुझाव भर दूंगा।

श्री सत्यपाल जैन : हम चुनाव में उनकी भागीदारी चाहते हैं और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने आपकी बात पर पूरा गौर किया है।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा-पूर्व) : आप चुनाव का पहला दौर दिल्ली में, दूसरा दौर जम्मू में और डाक द्वारा मतदान का तीसरा दौर श्रीनगर में करवा सकते हैं। यदि इस तरह से चुनाव सम्पन्न हों तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी।

श्री सत्य पाल जैन : आप इसे भली भांति जानते हैं। आपने उस प्रणाली का प्रयोग किया है। आपने उग्रवादियों के साथ जो बातचीत की है, उसके बारे में भी कृपया सदन को विश्वास में लीजिए। आपने सदन के भीतर यह बात कही है कि आपने उग्रवादियों से बातचीत की है। उग्रवादियों के किस समूह ने आपसे बातचीत की है? वे बातचीत क्या थीं? आपने उग्रवादियों से बातचीत की है लेकिन आपने उग्रवादियों से प्रभावित परिवारों से बातचीत नहीं की है। प्रधान मंत्री द्वारा यह कथन कि उन्होंने उग्रवादियों से बातचीत की है, एक बहुत ही गंभीर मामला है। कृपया सदन को विश्वास में लीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं प्रत्येक परिवार से अलग अलग तो बात नहीं कर सकता।

श्री सत्य पाल जैन : लेकिन आपने उग्रवादियों से बातचीत की है। वे बातें क्या थीं? मुद्दे क्या थे?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपको कम से कम यह बात समझनी चाहिए कि नौ वर्ष के बाद एक प्रधान मंत्री ने वहां जाने का साहस किया है।

श्री सत्य पाल जैन : हम उसकी सराहना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शाम के 7.30 बज चुके हैं। इतना काफी है।

श्री सत्य पाल जैन : आप स्वायत्तता के बारे में बात कर रहे हैं स्वायत्तता से आपका क्या तात्पर्य है?

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : जो भी स्वायत्तता दी जाएगी, वह संविधान के ढांचे के भीतर होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हमें इन ब्यौरों में जाने की कोई जरूरत है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं उस तरफ बैठे अपने मित्रों सहित इन महान सदन को केवल आश्वासन दे सकता हूं कि मैं वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और यदि संभव हुआ तो सितम्बर माह में अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव करवाने के लिए कदम उठाऊंगाए। इस आश्वासन के साथ, मैं उन सबसे इस संकल्प को सर्वसम्मति से अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 356 के अंतर्गत जारी की गई जम्मू और कश्मीर के संबंध में 18 जलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से प्रभावी 6 माह की और अवधि के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं :-

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई जम्मू और कश्मीर के संबंध मे 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से